खबर संक्षेप

हरिओम गोल्ड सेक्रेटरी अवार्ड से सम्मानित

सतना। अंतर्राष्ट्रीय समाजसेवी संस्था रोटरी क्लब 3120 द्वारा वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में आयोजित रोटरी डिस्ट्रिक अवॉर्ड फंक्शन में समाजसेवी हरिओम गुप्ता को डिस्ट्रिक गवर्नर सुनील बंसल द्वारा गोल्ड सेक्रेटरी अवार्ड से सम्मानित किया। रोटेरियन साथियों एवं इष्ट मित्रों सामाजिक बंधुओं ने हरिओम गुप्ता को बधाई दी है।

हिन्दू को हिंसक कहने वाले राहुल गांधी माफ़ी के लायक भी नहीं : कुलदीप

मैहर। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मैहर जिला के मंत्री कुलदीप तिवारी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सोमवार को संसद में हिन्दु समाज को लेकर दिए गए बयान के विरोध में मंगलवार को प्रदेश भर में प्रदर्शन कर पुतला जलाया गया और पूरे देश भर में इस बयान की काफी निंदा की गई है। जिसको लेकर के मैहर भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री कुलदीप तिवारी ने कहा कि संसद के अंदर हिंदू समाज को हिंसक बताना राहुल गांधी की हिन्दुओं के प्रति नफरत को जगजाहिर कर रहा है। श्री तिवारी ने कहा कि हिंदू समाज के प्रति घृणा से भरा राहुल गांधी का बयान अत्यंत निंदनीय और अपमानित करने वाला है। जिसका पूरा सनातनीय हिन्दू इसका विरोध करता है। जिसके लिए वह माफी के लायक भी नहीं है।

व्यापारियों में निराशा : कैट

सतना। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स 'कैट' मध्यप्रदेश के उपाध्यक्ष पवन मलिक ने कहा कि उप-मुख्यमंत्री जगदीश देवडा ने विधान सभा में प्रदेश का पूर्ण बजट पेश किया, 365067 करोड के बजट में ऐसा उल्लेख कहीं नहीं है कि उद्योग एवं व्यापार को बढाने के लिये इतनी राशि का प्रावधान किया गया और व्यापारियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये इस योजना के अर्न्तगत लाभ प्राप्त होगा। अतः यह बजट उद्योग और व्यापार के लिए उत्साह पैदा नहीं करता है। साथ ही जीएसटी लागू करते समय यह आश्वस्त किया गया था कि प्रोफेशनल टैक्स वापिस लिया जाएगा लेकिन अभी तक नही हुआ। पेट्रोलियम पर सीमावर्ती प्रदेशों के बराबर टैक्स की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। राज्य सरकार बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रही है, उद्योग एवं व्यापार में भी नया आकर्षण पैदा नहीं कर पा रही है।

अधूरी बनी हैं कई सड़कें, अधिकांश जगहों पर पैदल चलना मुश्किल

मटेरियल नहीं मिलने से सड़क बनाने का काम ठप, जहां देखो कीचड़ ही कीचड़

सतना। एक तरफ जहां स्मार्ट सिटी के लिए खोदी गईं सड़कों के कारण शहर की तस्वीर बदसूरत हो गई है वहीं दूसरी ओर जिन जगहों पर काम चल रहा है उन जगह पर काम बंद कर दिया गया है। बताते हैं कि जिस एजेंसी को मैटेरियल सप्लाई करने का ठेका दिया गया है उसे कंपनी के प्लांट में पिछले 15 दिन से खराबी आ जाने के कारण उत्पादन बंद हो गया है। जिसकी वजह से काम भी बंद पड़ा है। स्मार्ट सिटी का काम कर रहे अधिकारी बताते हैं कि मटेरियल नहीं मिलने की वजह से बड़ी समस्या है,यही कारण है कि हम अब खुदाई का काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि जितना काम अभी करना है उसके लिए ही मटेरियल नहीं मिल रहा है। काम करने वाले नर्मदा सिंह नामक कर्मचारी ने बताया कि प्लांट को ठीक करने का काम चल रहा है लेकिन बार-बार प्लांट बंद हो जाता है। पिछले दिनों इसी मामले में नगर निगम के इंजीनियर सिद्धार्थ सिंह ने बताया था कि हमने कई बार एजेंसी को नोटिस भी दिया है। लेकिन अभी तक निर्माण सामग्री नहीं मिल पा रही है।

शिकायतों का अंबार

दादा सुखेन्द्र सिंह स्टेडियम के पीछे स्थित जवाहर नगर विद्या विहार कॉलोनी का पिछले 7 महीने से हाल-बेहाल है यहां के लोग शिकायत करते-करते थक गए हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। एक अधिकारी ने बताया कि शिकायतों का अंबार है। बारिश का मौसम भी है। निर्माण सामग्री नहीं मिल रही है। हम करें भी तो क्या करें।

क्या कहते हैं लोग

शहर के नागरिक रामकुमार नामदेव कहते हैं कि सतना शहर में चल रहे सीवर लाइन प्रोजेक्ट और उसके गड्ढों से जनता हलाकान है। पूरे शहर की सड़कें खुदी पड़ी हैं। उनकी मिट्टी के कारण हर जगह कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है।सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है और आवागमन बुरी तरह प्रभावित है। आरंभ समिति ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन करते शहर के सिटी कोतवाली मार्ग पर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया और हवन कुंड में आहुतियां समर्पित कीं थी।प्रदर्शनकारी समिति सदस्यों ने नगर निगम के अधिकारियों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करते हुए सड़क पर बैठ कर हवन कुंड में आहुतियां दीं थी। समिति सदस्य ने कहा कि जिम्मेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।अंकित शर्मा रॉकी ने बताया कि सतना की जनता पिछले कई वर्षों से विकास के नाम पर परेशानी का सामना कर रही है।बिना किसी योजना के मनमानी तरीके से पूरे शहर में खुदाई का सिलसिला लगातार जारी है। कभी अमृत मिशन और जल वर्धन योजना के नाम पर तो कभी सीवर लाइन प्रोजेक्ट के नाम पर सड़कों को खोद कर फेंका जाता आ रहा है। उन्होंने बताया कि मलबा सड़क पर ही फैला रहता है।जिससे धूल-कीचड़ हो रहा है और फिसलन बढ़ने से हादसों की आशंका हर वक्त बनी रहती है। रिस्टोरेशन के नाम पर भी घटिया काम किया और कराया जा रहा है।शहर का हर व्यक्ति परेशान है लेकिन नगर निगम के जिम्मेदारों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इन्हीं दुर्दशा पूर्ण स्थितियों की तरफ ध्यानाकर्षण कराने के लिए ही आरंभ समिति ने सद्बुद्धि यज्ञ किया।

पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान की सतना में मौत

सतना। पैरा मिलिट्री फोर्स के एक जवान की सतना में मौत हो गई। पुलिस ने उस वक्त शिनाख्त न होने पर अज्ञात मानकर उसे दफन करा दिया लेकिन 20 दिन बाद अब पता चला है कि वह पैरामिलिट्री फोर्स का जवान था और बीच रास्ते से लापता हो गया था। हासिल जानकारी के मुताबिक सिटी कोतवाली अंतर्गत जवाहर नगर में जल संसाधन विभाग के कार्यालय के गेट के पास गत 12 जून की शाम एक व्यक्ति मृत हालत में पड़ा मिला था। मौके पर पहुंची पुलिस को उसके पास से ऐसा कोई दस्तावेज अथवा सामान नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराया और शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए। लेकिन जब दो दिन बाद भी कुछ पता नहीं चला तो पुलिस ने शव को अज्ञात समझ कर दफन करा दिया। हालांकि शिनाख्त की पुलिसिया कोशिशें जारी रहीं जिसके तहत पुलिस ने शव की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करवाई। इस तस्वीर पर झाबुआ पुलिस की नजर पड़ी तो वह तस्वीर उसे अपने यहां के एक मिसिंग पर्सन की होने का सन्देह हुआ। झाबुआ पुलिस ने संबंधित लापता व्यक्ति के परिजनों को बुलाकर तस्वीर दिखाई तो उन्होंने उसे पहचान लिया। मृतक की शिनाख्त भूरे सिंह भाबर निवासी मोहकपुरा तारखेड़ी जिला झाबुआ के रूप में उसकी पत्नी शारदा और भतीजे बाथू सिंह ने की। मृतक भूरे सिंह त्रिपुरा स्टेट राइफल्स की 7वीं बटालियन बीएनटीएसआर में आर्मी मैन के तौर पर कार्यरत था। फिलहाल उसकी पोस्टिंग अगरतला में थी। झाबुआ पुलिस ने इस बारे में सतना पुलिस से संपर्क कर अन्य जानकारियां साझा कीं। सिटी कोतवाली ने झाबुआ पुलिस से बताया कि भूरे सिंह को 9 जून को यूनिट से छुट्टी मिली थी। वह 9जून को ही अगरतला से भोपाल आने के लिए अपने रिजर्वेशन टिकट के साथ 01666 पर सवार हुआ था लेकिन 15 जून तक अपने घर झाबुआ नहीं पहुंचा। परिजनों ने यूनिट से संपर्क किया तो पता चला कि भूरे सिंह वहां से 9 जून को ही निकल गया था। परिजनों ने झाबुआ एसपी को ज्ञापन सौंपकर गुमशुदगी दर्ज कराई थी। झाबुआ पुलिस और यूनिट ने भूरे सिंह की तलाश शुरू कर रखी थी। उसकी लोकेशन भी ट्रेस कराई गई थी जिसमें 12 जून को उसकी लोकेशन सतना में पाई गई थी। इसके बाद जैसे ही सोशल मीडिया पर सतना पुलिस द्वारा पोस्ट कराई गई फोटो झाबुआ पुलिस के संज्ञान में आई तो उसे सन्देह हुआ नतीजतन मौत के 20 दिन बाद मृतक की शिनाख्त हुई जबकि सतना पुलिस कफ़न-दफन करा चुकी है।

20 दिन से लापता था,अगरतला से छुट्टी पर झाबुआ निकला था

जवाहर नगर कैसे पहुचा?

अगरतला से भोपाल के लिए निकला पैरामिलिट्री फोर्स का जवान आखिर सतना में कैसे उतरा और जवाहर नगर तक कैसे पहुंच गया? उसका सामान कहां गया और अगर उसकी आखिरी लोकेशन सतना में ट्रेस हुई थी तो फिर उसका मोबाइल फोन कहां गया? बताया जाता है कि जवाहर नगर में भूरे सिंह को जीवित अवस्था मे देखा था। कुछ लोगों ने उसकी मदद भी करने की कोशिश की थी लेकिन उसने मना कर दिया था। शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस को उसके शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं मिले थे।लिहाजा पीएम के बाद भी शिनाख्त न हो पाने पर पुलिस ने उसे दफन करवा दिया था। पोस्टमॉर्टम में भी डॉक्टर ने मौत की कोई ऐसी वजह नहीं स्पष्ट की।अब जब पहचान हो गई है तो परिजनों के सतना पहुंचने पर एसडीएम से अनुमति लेकर शव को कब्र से बाहर निकलवाया जाएगा। पुलिस यह जांच भी कर रही है कि मृतक सतना में क्यों उतरा और जवाहर नगर तक कैसे पहुंचा?

मेडिकल कॉलेज को मिलेगा पैसा रामवन पथ गमन का होगा विकास

सतना। मेडिकल कॉलेज के अच्छे दिन आने वाले हैं। इसकी माली हालत सुधरेगी। कॉलेज की शिक्षा के लिए महाविद्यालय की पुरानी चली आ रही मांग के बीच सतना को पीएम श्री कॉलेज की सौगात भी मिलेगी। इसके साथ ही 676 किमी लंबे विन्ध्य एक्सप्रेस वे का निर्माण भी किया जाएगा। मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने रतलाम,दतिया,शिवपुरी के साथ सतना मेडिकल कॉलेज के लिए भी 631 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बजट में प्रावधानित की गई इस राशि में से सतना के शासकीय मेडिकल कॉलेज के हिस्से में भी राशि आएगी। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह राशि सतना मेडिकल कॉलेज के लिए हॉस्पिटल बनवाए जाने की आवश्यकता पूर्ति पर खर्च की जाएगी अथवा इस रकम से कॉलेज की प्रशासनिक व्यवस्था और अन्य जरूरी खर्च किए जाएंगे।

रामवन गमन पथ की चिंता

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के रामवन पथ गमन के विकास पर भी फोकस किया है। बजट में श्रीराम वन गमन पथ को विकसित करने का संकल्प व्यक्त किया गया है। जिसके तहत उन स्थानों को चिन्हित और विकसित किया जाएगा जहां भगवान राम ने वनवास काल के दौरान समय व्यतीत किया था। भगवान श्रीराम ने वनवास काल में सर्वाधिक साढ़े 11 साल का

समय जिले के चित्रकूट क्षेत्र में व्यतीत किया था। इस अंचल में भगवान की स्मृतियां जगह जगह बिखरी पड़ी हैं। उम्मीद है कि सरकार के इस प्रोजेक्ट से इन तमाम पौराणिक और धार्मिक महत्व की धरोहरों को संरक्षित किया जा सकेगा। वित्त मंत्री ने प्रदेश के हर जिले में पीएम श्री कॉलेज खोले जाने की भी घोषणा की है जिसका फायदा सतना को भी निश्चित तौर पर मिलेगा। सतना जिला मुख्यालय में एक और शासकीय महाविद्यालय की आवश्यकता पिछले काफी समय से महसूस की जा रही है। पीएम श्री कॉलेज के जरिये छात्रों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब मैहर भी सतना से पृथक होकर अलग जिला बन चुका है लिहाजा एक पीएम श्री कॉलेज मैहर में भी बनेगा। इसके अलावा सतना,रीवा,सीधी,सिंगरौली समेत विन्ध्य के जिलों को 676 किमी लंबे विन्ध्य एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा।

प्रिज़्म को मिला ग्लोबल सीएसआर सस्टैनिबिल्टी ईएसजी अवॉर्ड

सतना। प्रिज़्म जॉनसन लिमिटेड मनकहरी को सीएसआर के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण,जल संरक्षण के क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट कार्यो के लिए ब्रांड होनचोस द्वारा वेस्ट सीएसआर प्रोजेक्ट 2024 (इनवायरनमेंट) कटेगरी में भाजपा के प्रवक्ता अरुण मिश्रा,ब्रांड होनचोस के डायरेक्टर गौरव भल्ला एवं सिवानी कपूर एडीटर इन चीफ द्वारा ट्राफी एवं प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया है। जिसे प्रिज़्म जॉनसन लिमिटेड के एजीएम सीएसआर एवं जनसंपर्क देवेन्द्र मिश्रा एवं संजय सिंह परिहार ने प्राप्त किया। यह अवार्ड समारोह होटल हयात रीजेन्सी गुरुग्राम हरियाणा में 29 जून 2024 को सम्पन्न हुआ जिसमें देश भर की नामी गिरामी कंपनियों के लगभग 200 नामिनेशन में से प्रिज़्म जॉनसन लिमिटेड द्वारा किये गये कार्यों को इस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार के लिये चुना गया। सीएसआर के अंतर्गत पर्यावरण के क्षेत्र में वेस्ट सीएसआर प्रोजेक्ट के लिए मिले अवार्ड पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विजय अग्रवाल,कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ विवेक अग्निहोत्री,चीफ आपरेटिंग आफीसर राकेश जैन,मनीष कुमार सिंह (प्रेसीडेंट एवं प्लांट हेड) एवं मनीष कुमार सिन्हा (सीनियर वाइस प्रसीडेंट एचआरएम एंड कार्पोरेट अफेयर्स) सहित कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में भी कंपनी पर्यावरण के क्षेत्र में अनवरत उत्कृष्ट कार्य करती रहेगी। उपरोक्त आशय की जानकारी प्रिज़्म जॉनसन लिमिटेड के एजीएम जनसंपर्क देवेन्द्र मिश्रा ने दी है।

दीक्षा आरंभ समारोह में कई लोगों को किया गया सम्मानित

मैहर। पीएम कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस,शासकीय विवेकानंद महविद्यालय मैहर में दीक्षा आरंभ समारोह के तीसरे दिन कार्यक्रम का प्रारंभ गणेश वंदन एवं सरस्वती वंदना से हुआ।डॉक्टर एके गौतम प्राचार्य द्वारा अतिथि रामकुमार रजक पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष एवं अन्य प्राध्यापकों का सम्मान किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत में पहला व्याख्यान संवैधानिक मौलिक कर्तव्य पर डॉक्टर त्रिपुरेस पाठक द्वारा दिया गया। उन्होंने संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य पर विस्तृत चर्चा की गई जिसमें बताया गया राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। सूचना के अधिकार पर व्याख्यान डॉक्टर उपेंद्र पांडे द्वारा दिया गया। जिसमें उन्होंने सूचना लेने के लिए प्रावधान पर विस्तृत चर्चा की इसके लिए फीस कितना लगेगा तथा कौन सी सूचना निकलेगी इस पर भी चर्चा की गई। महिलाओं की यौन उत्पीड़न समस्या निवारण समिति की संयोजक डॉक्टर सुनीता राज खन्ना ने इस विषय पर विस्तृत विवेचना की उन्होंने इसके अधिनियम तथा इस अधिनियम के तहत सभी बातों से सभी को अवगत कराया। साइबर एवं भौतिक संपदा का अधिकार की जानकारी शैलेश सिंह पुस्तकालय प्रभारी द्वारा दी गई। अपने साइबर सुरक्षा तथा साइबर अपराध पर भी विस्तृत चर्चा की। स्वास्थ्य एवं कल्याण पर विस्तृत चर्चा डॉक्टर जितेंद्र तिवारी बीएएमएस द्वारा किया गया।आपके द्वारा अच्छे स्वास्थ्य,रहन-सहन, दिनचर्या,योग एवं आसन तथा विभिन्न बीमारियों से बचने हेतु कई उपाय बताए गए।सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक उन्मुखीकरण पर व्याख्यान डॉक्टर आर.पी.मिश्रा द्वारा किया गया। मानसिक स्वास्थ्य एवं परामर्श पर व्याख्यान मनोविज्ञान के प्रोफेसर शैलेंद्र प्रताप द्वारा दिया गया।मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के टिप्स उनके द्वारा दिए गए जैसे अच्छा भोजन, अच्छी नींद,योग एवं व्यायाम आदि पर विशेष जोर दिया गया। खेल विधा की जानकारी डॉ सुनील मुँडेर तथा योग के विषय में सुनील अहिरवार द्वारा जानकारी प्रदान की गई। छात्रावास एवं परिवहन व्यवस्था पर जानकारी डॉक्टर राजेश सिंह प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र द्वारा दिया गया। विभिन्न क्लब एवं समितियां डॉक्टर एके सिन्हा प्राध्यापक समाजशास्त्र द्वारा दी गई जिसमें अनुशासन समिति,रेड रिबन क्लब,एंटी रैंकिंग समिति ,छात्र समस्या निवारण समिति,हेल्पडेस्क की जानकारी प्रदान की गई।अनुसंधान के अवसरों पर व्याख्यान डॉक्टर गिरीश राय प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र द्वारा दिया गया। समूह गतिविधि एवं समूह निर्माण पर व्याख्यान डॉक्टर फरीदा खातून अतिथि विद्वान द्वारा दिया गया। पूर्व छात्र संगठन के बारे में जानकारी डॉक्टर एके सिन्हा द्वारा बताई गई। पूर्व छात्र अन्नपूर्णा एवं पूर्व छात्र पूर्णिमा सिंह द्वारा अपने अनुभव शेयर किया गया। आप लोग के द्वारा निर्भीक होकर शिक्षा प्राप्त करने पर जोर दिया गया तथा गुरुजनों का सदा आदर करें तथा उनके बताएं मार्ग पर चलने की सलाह दी। इसके बाद मनोरंजन खेल एवं प्रदर्शन के लिए डॉक्टर रीता घोष एवं डॉ मंजू लता श्रृंगी के द्वारा महाविद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं में आयोजित करवाने हेतु प्राचार्य महोदय से अनुरोध किया गया जैसे मेहंदी प्रतियोगिता एवं व्यंजन की प्रतियोगिता आयोजित की बात कही। डा.मंजू शर्मा एवं ज्योति मालवीय द्वारा युवा उत्सव की जानकारी दी गई। मनोरंजन कार्यक्रम के तहत पूजा सिंह द्वारा भजन तथा दो छात्राओं द्वारा बधाई नृत्य पेश किया गया।अंत में तीन दिवसीय कार्यक्रम के समापन की घोषणा डॉक्टर एस के पांडे द्वारा अध्यक्षीय उद्बोधन प्राचार्य डॉक्टर ए के गौतम द्वारा किया गया।आभार प्रदर्शन राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया।

अल्पसंख्यक कल्याण दर्जा प्राप्त विद्यालयीन शिक्षण संस्थाओं की मान्यता रद्द हो

सतना। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला पंचायत सभागार में आयोजित मैहर जिले की समस्त (07) अल्प संख्यक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं की मान्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए जिला पंचायत सतना की स्थायी शिक्षा समिति ने जिला परियोजना समन्वयक और सहायक संचालक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के माध्यम से कलेक्टर सतना मैहर के पास नोटशीट के माध्यम से अल्पसंख्यक दर्जा निरस्त करने के निर्देश दिये। ज्ञात हो कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती सुष्मिता डॉ.पंकज सिंह परिहार के नेतृत्व में स्थायी शिक्षा समिति ने सतना व मैहर जिले में संचालक अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त सभी संस्थाओं से सम्बन्धित दस्तावेज माँगे थे। संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों में कोई भी संस्था मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी प्रमाण पत्र व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही कर पाई। किसी भी संस्था में भारत सरकार अथवा मध्य प्रदेश शासन द्वारा 25 फीसद के न्यूनतम अल्पसंख्यक छात्र व छात्राओं के प्रवेश के नियम का पालन नहीं किया। सतना मैहर जिले की अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त संस्थाओं ने 25 फीसद न्यूनतम अल्प संख्यक छात्र प्रवेश के नियम के विरुद्ध

निम्नानुसार प्रवेश दिये:-

संस्था का नाम एवं पता

क्राइस्ट ज्योति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सतना,डी.पाल विद्यालय माधवगढ़

अल्पसंख्यक,किस्तुकुला मिशन हायर सेकेण्डरी विद्यालय सतना,सेन्ट क्लारेन्ट विद्यालय बारा कला सतना,संथाम हॉयर सेकेण्डरी विद्यालय मैहर स्नेह सदन विद्यालय सतना अप्राप्त,निर्मल माता स्कूल कैलाशपुर सतना अप्राप्त संस्थाओं द्वारा प्राप्त उपरोक्त जानकारी से यह सिद्ध हो गया कि सतना जिले में अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त संस्थाओं के नाम पर कई नामी गिरामी विद्यालय नियमों को ताक पर रख कर लाखों रुपयों की शुल्क वसूली के माध्यम से नियम विरुद्ध शिक्षा की दुकान चलाते रहे। उपरोक्त संस्थाओं के नियम विरुद्ध संचालन पर संज्ञान लेते हुये जिला पंचायत की स्थायी शिक्षा समिति ने नियमानुसार सतना और मैहर जिले में संचालित सभी अल्प संख्यक दर्जा प्राप्त संस्थाओं का अल्पसंख्यक दर्जा निरस्त कर मान्यता समाप्त करने के निर्देश के साथ जिला परियोजना समन्वयक और सहायक संचालक अन्य पिछड़ा वर्ग को कलेक्टर मैहर और सतना को नोटशीट पुटप करने को कहा है।बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती सुष्मिता डॉ.पंकज सिंह परिहार, शिक्षा समिति के सदस्यः-संजय सिंह,आरती चौधरी,प्रियंका वर्मा एकता सिंह,डॉ.पंकज सिंह परिहार,जिला परियोजना समन्वयक-विष्णु त्रिपाठी,सहायक संचालक अन्य पिछड़ा वर्ग के.के.शुक्ला,दिवाकर सिंह,दान बहादुर सिंह सहित सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं के संचालक व मैनेजर उपस्थित रहे।

खबर संक्षेप

विधायक राजेश वर्मा के जन्मदिन पर भाजपाइयों ने बांटे फल एवं किया वृक्षारोपण

देवेंद्रनगर। गुनौर के लोकप्रिय विधायक राजेश वर्मा जी के जन्मदिन पर मंडल भाजपा देवेंद्र नगर द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मे डॉक्टर अभिषेक जैन की उपस्थिति में भर्ती मरीजों को फल बांटे गए एवं उनके अच्छे स्वास्थ की शुभकामनायें की गई एवं वर्मा जी के जन्मदिन पर वृक्षारोपण किया गया इस कार्यक्रम मे भाजपा मंडल हीरा जी पटेल, वरिष्ठ नेता उमेश शर्मा,आशीष तिवारी, शैलेश कुमार अग्रवाल, निक्की जायसवाल उमेश पाठक धीरेंद्र बागरी अरुण तिवारी सहित पत्रकार गण उपस्थित रहे।

विधायक ने उठाई इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग

पन्ना। पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने पन्ना विधानसभा को लेकर विधानसभा में पूछे प्रश्न क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय में विद्यार्थियों की

सुविधा हेतु बस एवं हॉस्टल को उपलब्ध कराने तथा पन्ना जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज को शुरू किए जाने को लेकर विधानसभा में प्रश्न पूछा साथ ही जिले माइनिंग हेतु वन विभाग की भूमि हस्तांतरण को लेकर एवं पन्ना जिले में डायमंड पार्क शीघ्र चालु कराए जाने को लेकर भी विधानसभा में प्रश्न पूछा जिस पर विधानसभा से कृषि महाविद्यालय हेतु छात्राओं के बस एवं भवन जैसी सुविधा अगले आवंटन में शुरू हो जाएगी वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज की कार्यवाही प्रचलन में है तथा डायमंड पार्क के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है शीघ्र ही डायमंड पार्क भी खोला जाएगा को लेकर मिला आश्वासन पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह को विकास के लिए जाना जाता है और वह विकास के लिए सतत रूप से प्रयास करते रहते हैं। विधानसभा में विधायक की भूमिका एक बार फिर विकास को लेकर प्रयासरत को लेकर जानी गई।

खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित

पन्ना। भारत सरकार एवं म.प्र. शासन की अतिमहत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना अंतर्गत इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 18 वर्ष एवं अधिक आयु के कोई भी शिक्षित बेरोजगार युवा योजना का लाभ लेकर स्वयं का उद्यम स्थापित कर सकते हैं। इस योजना में बैंक से प्रदान ऋण में उद्यानिकी विभाग द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत राशि का 35 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम 10 लाख रूपए जो भी कम हो स्वीकृत किया जाता है। स्वरोजगार के इच्छुक उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त कर दाल मिल, आटा मिल, चावल मिल, बरी, पापड़, अचार, मुरब्बा जैम, जेली, केचप, सिरका, ऑयल मिल, बेकरी प्रोडक्ट, कुरकुरे, चिप्स आदि किसी भी प्रकार की इकाई स्थापित कर सकते हैं। योजना की अधिक जानकारी के लिए उद्यानिकी विभाग के जिला कार्यालय अथवा विकासखण्ड में स्थापित उद्यानिकी रोपणी में संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उद्यमी को बैंक ऋण दिलाने में सहयोग के लिए विकासखण्ड स्तर पर जिला रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति भी की गई है। गौरतलब बात यह है कि वर्तमान समय में उद्योग स्थानीय स्तर पर लगाकर स्वयं रोजगार तो पा ही सकते है वहीं दूसरों को भी रोजगार प्रदान करने में सहायक होने को लेकर जाना जाता है।

शासकीय भूमि में स्थापित होंगे अंकुर उपवन

पन्ना। पर्यावरण विभाग द्वारा प्रत्येक पंचायत और नगरीय निकाय में शासकीय भूमि पर अंकुर उपवन की स्थापना के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। उपवन में आम नागरिक विशेष तिथियों जैसे जन्म दिवस, वैवाहिक वर्षगांठ अथवा अन्य विशिष्ट तिथियों में पौधरोपण कर सकते हैं। साथ ही पौधों की सुरक्षा का संकल्प भी लिया जाएगा।

प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया गया बजट जन कल्याण को समर्पित: ब्रजेंद्र प्रताप सिंह

विधायक हम पूरे मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव द्वारा की सरकार द्वारा पेश किया गया बजट जन कल्याण को समर्पित बजट है।बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा गया।

पन्ना।

उन्होने कहा कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री और प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत किए गए मध्य प्रदेश के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि कर प्रदेश की जनता को सर्वांगीण विकास का तोहफा दिया। प्रस्तुत बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में 21,144 करोड़ से अधिक की वृद्धि कर आगामी 2 वर्षों में 11 नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे। यह अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान कर श्रवण कुमार का फर्ज बखूबी निभाएंगे। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वन एवं पर्यावरण के लिए 4725 करोड़ का प्रावधान किया है। सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि के भुगतान की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने से सेवानिवृत कर्मचारियों को भत्ते तत्काल और सुगमता से मिलेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया बजट का में लोकसभा की जनता जनार्दन की ओर से अभिनंदन करता हूं।

सिंचाई और सड़कों के लिए मिला पर्याप्त बजट - ब्रजेंद्र मिश्रा

भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री बृजेंद्र मिश्रा ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि आगामी 5 वर्षों में मध्य प्रदेश में विश्व स्तरीय सड़कों का जाल बिछने जा रहा है, जिसमें अटल प्रगति पथ पर 299 किलोमीटर, नर्मदा प्रगति पथ पर 900 किलोमीटर, विंध्य एक्सप्रेस वे पर 676 किलोमीटर, मालवा निमाड़ विकास पथ 450 किलोमीटर, बुंदेलखंड विकास पथ 330 किलोमीटर और मध्य भारत विकास पथ को 746 किलोमीटर की विश्व स्तरीय सड़के मिलने जा रही हैं केवल इतना ही नहीं किसने की आए दुगना करने के लिए प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र के रकवा एक करोड़ हेक्टेयर से अधिक होने वाला है। वर्तमान में सिंचित क्षेत्र का रकबा 50 लाख है, जिसे आगामी वर्षों में बढ़कर 1 करोड़ हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके लिए बजट में 13596 करोड़ का प्रावधान किया गया। श्री मिश्रा ने कहा कि विधानसभा में जो बजट प्रस्तुत किया गया वह डॉक्टर मोहन यादव जी के कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। इस बजट में 36,5 67 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट की प्रमुख विशेषता यह रही की इस सत्र में देश की जनता जनार्दन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नया कर नहीं लगाया गया है, लेकिन कोई नया कर ना लगाते हुए भी संसाधनों में 16 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करते हुए प्रदेश को विकसित, समृद्धशाली और जनकल्याणकारी बनाने में कोई कसर कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। जिसके लिए मैं क्षेत्र की जनता की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का अभिनंदन करता हूं।

विद्यार्थियों के लिए पेश किया गया बजट कल्याणकारी - राजेश वर्मा

भारत स्काउट एवं गाइड के जिला अध्यक्ष सुरेंद्रमणि दुबे ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया गया बजट छात्र एवं छात्राओं के लिए कल्याणकारी बजट है, जिसमें छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए नए-नए विद्यालय, छात्रावास, स्कॉलरशिप एवं निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी की गई।

नव प्रवेशित विद्यार्थियों का अभिप्रेरण कार्यक्रम के तहत तीन दिवसीय मार्गदर्शन कार्यक्रम सम्पन्न

पन्ना।

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस, छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना में नवप्रवेशित विद्यार्थियों हेतु अभिप्रेरण कार्यक्रम के तृतीय दिवस में विद्यार्थी जीवन और सहायता प्राणली, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां, परिचय एवं मार्गदर्शन पर कार्यक्रम कराया गया। सभी महत्वपूर्ण गतिविधियां, संवैधानिक मौलिक कर्तव्य, सूचना का अधिकार, विद्यार्थी एवं क्लबों एवं सोसायटी का परिचय, महिलाओं की यौन उत्पीड़न, अनुसंधान के अवसरों का परिचय विषय पर व्याख्यान आयोजित हुए। मुख्य अतिथि के रूप में संस्था के पूर्व प्राचार्य एच.एस.शर्मा ने छात्रों को अनुशासन का महत्व बताते हुए विद्यार्थी जीवन में सफलता के सूत्र बताये। संस्था के प्राचार्य एवं संरक्षक डॉ एस पी एस परमार ने नवप्रवेशित छात्रों का मार्गदर्शन किया। उपरोक्त कार्य्क्रम का संचालन डॉ; श्वेता ताम्रकार सहायक प्राध्या पक रसायन शास्त्र ने किया। कार्यक्रम में डॉ. पी.पी. मिश्रा, प्रशासनिक अधिकारी, डॉ. जे;के; वर्मा, डॉ. विनय श्रीवास्तव, डॉ. आर.एम.दत्तॉ, डॉ. कविता परवंदा, डॉ. अंकिता सोनी, डॉ. आंनद चौरसिया, डॉ. पुष्पराज सिहं, डॉ. मनोज शुक्ला, डॉ. सिद्धू सिंह, डॉ. मंयक सिंह, धर्मेन्द्र यादव डॉ. शिवगोपाल सिंह डॉ. अरविंद मण्डेलिया, डॉ. पियूषा शर्मा एवं अन्यू प्राध्यापक गण उपस्थित रहे।

म.प्र. शासन लिखी गाड़ियां चर्चा में, आखिर मापदण्ड का पालन कौन करायेगा?

पन्ना। जिले के विभागीय अधिकारियों को जो वाहन सरकार के द्वारा सुविधा के रूप में उपलब्ध कराये जाते है उसके मापदण्ड आखिरकार पालन कराने को लेकर जिम्मेदार कौन ? जहां अधिकारियों के कार्यालयों में जो वाहन लगाये जाते है क्या मनमानी हालात या फिर टैक्सी परमिट की कोई आवश्यकता नहीं वहीं म.प्र. शासन लिखा गाड़ियों में कहीं भी नजर आ जाती है आखिरकार किराये के वाहन अगर लगाये जाते है तो उनके लिये मापदण्ड का पालन कराने को लेकर जिम्मेदार कौ।

जिले में अधिकारियों को जहां वाहन सुविधा सरकार के द्वारा पहले तो शासकीय स्तर पर शासकीय वाहन मिलते थे हालात बदले अब निजी वाहन किराये पर विभागीय अधिकारी अपने सुविधानुसार कार्यालयों में लगाते है लेकिन इसके पीछे मापदण्ड क्या है क्या यह मनमाने हालात या खुली छूट

अधिकारियों को कोई भी वाहन लगाने की वहीं टैक्सी परमिट क्या जरूरी या नहीं साथ ही म.प्र. शासन गाड़ियों में लिखवा दिया जाता है वह वाहन भले ही वाहन मालिक के पास पहुंच जाता है या फिर ड्राइवर कहीं भी लेकर घूमते है। म.प्र. शासन का सेंबल अंकित करके हालात वाहनों के आये दिन चर्चाओं में नजर आ रहे है। आखिर इसके पीछे अधिकारियों के द्वारा नियमों का पालन करने को लेकर क्या उचित नहीं माना जाता या फिर अब कोई नियम ही नहीं बिना टैक्सी परमिट के ही खुलेआम म.प्र. शासन लिखकर कोई भी गाड़ी कोई भी अधिकारी अपने यहां लगा सकते है क्या? सड़कों में नजर आ जाती है इन वाहनों की दास्तां जो बिना पीली प्लेट जो टैक्सी परमिट की होती है नेम प्लेट की उसका कोई उल्लेख नहीं होता वहीं म.प्र. शासन जरूर नजर आ जायेगा। खुलेआम सड़कों में ऐसी गाड़ियां नजर आती है जो चर्चा का विषय बनती है आखिर म.प्र. शासन की आड़ में इन गाड़ियों का इस्तेमाल कौन और कब कर रहा है इसका जिम्मेदार कौन क्या इन पर होगी नजर या की जायेगी पड़ताल कितने वाहन विभागीय अधिकारियों के द्वारा जो लगाये गये है उनमें नियमों का पालन किस हालात में किया गया है। यह तो जिम्मेदार ही जानें।

जल मित्रों ने ग्राम पंचायत में तैयार की नर्सरी

पौधारोपण ही जल संरक्षण का कारगर उपाय

पौधों से ही जमीन में उतरेगा पानी सभी ग्राम पंचायतों में तैयार हो पौधरोपणी

पन्ना।

स्वयंसेवी संस्था समर्थन जल संरक्षण पर लगातार काम कर रही है। पन्ना जनपद में किचेनगार्डन को बढ़ावा देने के बाद पौधरोपणी तैयार कर ग्राम पंचायत को आतमनिर्भर बनाने के साथ युवा जलमित्रो को पर्यावरण के प्रति प्रेरित करने का काम भी कर रही है। ग्राम पंचायत दिया, जरधोवा, तारा, सुन्दरा, फुलवारी, इटवाल्हि, मनौर के जलमित्रो ने लगभग 17 हजार पौधे आवंला, पपीता, मुनगा, तीताफल, अमरूद के तैयार किये है।

ग्राम पंचायतो को गांव में ही मिलेंगे पौधे

ग्राम पंचायत दिया के सरपंच रामशिरोमणि सिंह सिंगरोल, जरधोवा सरपंच रामरानी गोंड, तारा सरपंच बैजनाथ ने कहा की जलमित्रो के प्रयास बहुत ही सराहनीय है हमे अपनी पंचायत में पौधे मिल जायेगे और बाहर से नही खरीदना पडेगा। 10 से 20 रू में हम सब पौधा खरद लेगे। कल जरधोवा में 41 मुनगे के पौधे 410 रू में विक्रय किये जलमित्र इस पैसे से पुनः सब्जी किचेनगार्डन को लगाने में सहयोग करेगे।

ग्रे वाटर एवं जल प्रबंधन है लक्ष्य

जलमित्रो का कहना हे की हम समर्थन के साथ जुड़ कर पर्यावरण एवं पानी को उगाने का काम कर रहे है पिपलान्त्री जैसी पंचायत जो पानी के संकट से उबर आयी है हम भी अपने जिले को पानी के संकट से उबारने में सहयोग करेगे। संपूर्ण कार्यक्रम में समर्थन टीम एवं जलमित्र के साथ ग्राम पंचायत के सरपं सहयोग कर रहे है। संस्था चाहती है की सभी ग्राम पंचायतों में अपनी स्वयं की ''पौध रोपणी '' तैयार हो।

पेंशनर समाज तहसील इकाई अमानगंज ने किया शोक व्यक्त

बालाजी सरकार में बैठक संपन्न

अमान गज पन्ना। मध्य प्रदेश सेवा मुक्त कर्मचारी संघ पेंशनर समाज तहसील इकाई अमानगंज ने आज दिनांक 3 जुलाई को नगर के प्रमुख धार्मिक स्थल श्री श्री 1008 श्री बालाजी सरकार मंदिर में अपनी संगठन की बैठक आयोजित की, जहां बैठक में संगठन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की और संगठन से जुड़े सक्रिय सदस्यों की गत मह में हुई मृत्यु को लेकर एक शोक सभा आयोजित की और उन्हें शोक श्रद्धांजलि देकर उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की। बैठक की अध्यक्षता मिथिलेश द्विवेदी पूर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा की गई। जबकि बैठक में संगठन के अध्यक्ष अवधेश चतुर्वेदी ने बताया कि संगठन से जो कार्य अभी शेष हैं उस विषय में चर्चा कर तेजी से कार्यवाही करने हेतु सभी को एकजुट होना होगा और तत्कालीन मुक्त हुए कर्मचारियों को भी संगठन में जोड़ना होगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से तहसील अध्यक्ष अवधेश चतुर्वेदी, मिथिलेश द्विवेदी, धर्मदास गर्ग, पूरन तिवारी, सुरेंद्र सिंह तोमर, काशी प्रसाद राजपूत, कन्हैया लाल पटेरिया आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी संगठन के सदस्यों ने संयुक्त रूप से बालाजी सरकार को प्रसाद अर्पण कर सभी साथियों के स्वस्थ रहने की कामना की।

मुख्यमंत्री की घोषणा शीघ्र पूरी हो

अमानगंज अस्पताल को दिलाया जाए सिविल अस्पताल का दर्जा

अमान गज पन्ना।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नगर अमानगंज में की गई घोषणा आज भी लंबित है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था की जनसंख्या बहुसंख्यक क्षेत्र अमानगंज के आसपास 118 ग्राम जो चिकित्सा सुविधा की वाट जोहते हैं इन्हें लाभान्वित कराए जाने हेतु शीघ्र अमानगंज अस्पताल को सिविल अस्पताल अगले वित्तीय वर्ष में कायम किया जाएगा परंतु आम जनमानस की धारणा के अनुरूप तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वादा आज भी अधूरा है कई बार विभागीय सर्वेक्षण कराया गया परंतु वित्तीय संकट हो या जो भी समस्याएं हो इसका क्रियान्वयन आज भी लंबित है जो तत्काल पूरा होना अति आवश्यक है बीते दिवस क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान हमारे मैदानी संवाददाता से हुए साक्षात्कार के दरमियान मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ जिला पन्ना के आजीवन सदस्य और जिला प्रवक्ता डॉक्टर एमपी पांडेय ने बताया कि उन्होंने क्रमांक 59 के युवा कर्मठ ओजस्वी विधायक डॉ राजेश वर्मा के निवास पर जाकर एक सूत्रीय ज्ञापन सौंपा जिसमें लिखा गया है कि शासन की धारणा के अनुरूप विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ एवं पैरामेडिकल स्टाफ कुल मिलाकर 50 कर्मचारी जो नियुक्त होते हैं इनका

अमानगंज अस्पताल के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय के माध्यम से अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग वल्लभ भवन सचिवालय पांचवी मंजिल भोपाल को सादर समप्रेषित करें। डॉ पांडेय के अनुसार वर्ष 1984-85 में तत्कालीन गृहमंत्री कैप्टन जयपाल सिंह द्वारा कई बार लिखे जाने के बावजूद भी अमानगंज अस्पताल के सिविल अस्पताल बनने की मांग पूरी नहीं हो सकी। जिससे 80-90 वर्ष के बुजुर्ग छोटी-छोटी बीमारियों के लिए भी दवा कराने के लिए पन्ना, सतना, रीवा, नागपुर ग्वालियर रेफर किए जाते हैं जो अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है। डॉक्टर पांडे के अनुसार मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव अपनी कैबिनेट में इस बिंदु को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर समय सीमा 90 दिवस के भीतर 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल एवं 10 बिस्तर आयुष चिकित्सालय अमानगंज अस्पताल के इसी प्रांगण में विभिन्न विषयों के विशेष एवं पैरामेडिकल स्टाफ के लिए स्वीकृति हेतु वित्तीय संधारण प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश कराए जाने के साथ ही आम जनमानस की मांग को पूरा करें। ऐसी चर्चाएं जन कल्याण के दायरे में चाय की दुकानों पर, बाजार व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, शिक्षित बेरोजगार सभी वर्ग के लोगों में उक्त चर्चाएं और सुनाई दे रही हैं।

तेज रफ्तार बोलेरो कार ने टक्कर मार गाय को उतारा मौत के घाट

देर रात घटी घटना

अमान गज पन्ना। पन्ना जिले के अमानगंज छतरपुर सड़क मार्ग पर बीती रात नगर से तकरीबन आधा फलनाग दूर एक तेज रफ्तार बोलेरो कार जो छतरपुर से सीधे अमानगंज प्रवेश कर रही थी और प्रवेश करते ही उसने एक गाय को टक्कर मार दी जिससे गाय की मौके पर ही मौत हो गई बोलेरो कार चालक तेज रफ्तार में था जो सीधा टक्कर मारते हुए गांधी चौक की ओर निकल अज्ञात स्थान की ओर भाग गया। घटना को देख वार्ड क्रमांक 1 पतारा और दुबे मोहल्ला के लोग घटनास्थल पर जुड़ गए, जिन्होंने घटना की सूचना रात को ही स्थानीय पुलिस थाना अमानगंज में दी कार चालक कौन था इस विषय में अब तक किसी को कोई भी जानकारी नहीं मिली मौके पर उपस्थित राहगीरों ने बताया की कार चालक अत्यंत शराब के नशे में था जो इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी किसी हालत में घटना घटित कर सकता है अगर समय रहते इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो स्थानीय जनता में आक्रोश व्याप्त है।

कलेक्टर ने म.प्र. पर्यटन क्विज पोस्टर का किया विमोचन

प्रतियोगिता के लिए 8 जुलाई तक होंगे पंजीयन

पन्ना।

मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड एवं जिला प्रशासन के तत्वाधान में प्रदेश के समृद्धशाली इतिहास, परंपराओं, ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक विविधताओं, कला, प्राकृतिक समृद्धि, महापुरुषों एवं पर्यटन महत्व की संभावनाओं से छात्र-छात्राओं को अवगत कराने तथा पर्यटन के माध्यम से जागरूक करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय पर्यटन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 27 जुलाई को किया जाएगा। इसके लिए सभी स्कूल प्राचार्यों को लिंक के जरिए 8 जुलाई तक तीन-तीन विद्यार्थियों के पंजीयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के विजेता राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिला स्तरीय प्रतियोगिता दो स्तर पर आयोजित होगी, जिसमें सर्वप्रथम लिखित परीक्षा में प्रथम 6 स्थान प्राप्त करने वाली टीमें मल्टीमीडिया राउंड में सम्मिलित होंगी। प्रथम तीन टीमें विजेता एवं शेष तीन टीमें उप विजेता घोषित होंगी। इन सभी छह टीमों को प्रमाण पत्र, कूपन एवं मेडल के साथ ही मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों का मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के माध्यम से भ्रमण करने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही सभी सम्मिलित प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कलेक्टर सुरेश कुमार द्वारा आज कलेक्टर कक्ष में क्विज के लिए राज्य स्तर से प्राप्त पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पर्यटन क्विज प्रतियोगिता के जिला प्रभारी अशोक चतुर्वेदी, जिला शिक्षा अधिकारी एवं डाइट प्राचार्य रविप्रकाश खरे, सहायक संचालक शिक्षा अमित जैन, क्विज मास्टर रामकिशोर गर्ग उपस्थित रहे।

खबर संक्षेप

महाराजपुर विधायक की पहल पर सीएम स्वेच्छानुदान राशि स्वीकृत

नौगांव। महाराजपुर विधायक कामाख्या प्रताप सिंह की अनुशंसा पर जनपद क्षेत्र की कैंसर पीड़ित महिला के इलाज के लिए मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महाराजपुर क्षेत्र के विधायक कामख्या प्रताप सिंह के पत्र पर विधानसभा अंतर्गत ग्राम रगौली की रहने वाली पानकुंवर राजपूत के कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 1 लाख रुपए की स्वेच्छानुदान राशि स्वीकृत की गई है। जिसके लिए महाराजपुर विधायक कामकाख्या प्रताप सिंह ने 18 जून को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम पत्र लिखकर कर श्रीमती पानकुंवर राजपूत निवासी ग्राम रगौली पोस्ट इमलिया जो कि गंभीर कैंसर रोग से पीड़ित है, जिनका इलाज लगातार भर्ती होकर जवाहरलाल नेहरू केन्सर हॉस्पिटल भोपाल में चल रहा है। विधायक के अनुशंसा पत्र के आधार पर मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से 1 लाख रूपए की राशि स्वीकृत हो गई है जिससे महिला अपना इलाज अब आसानी से कर पाएगी।

चौकी के स्थानांतरण को रोकने ग्रामीणों ने एसपी को दिया ज्ञापन

छतरपुर। बमीठा थाना क्षेत्र के लगभग 8 ग्रामों के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी को आवेदन देते हुए ग्राम सीलोन में स्थित चौकी को यथावत रखने की मांग की है। ग्रामीणों ने एसपी को दिए आवेदन में बताया कि सीलोन में पुलिस चौकी की स्थापना 1981 में उस समय की गई थी जब लोकपाल सिंह द्वारा सात हत्याएं की गई थीं। चौकी की स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के आदेश से की गई थी। इस चौकी से ग्राम सीलोन, कावर, करोंदया, भुसार, मझोटा, खरयानी, रनगुवां बरद्वाहा, गंगवाहा के निवासियों को सुरक्षा प्रदान होती है। यदि उपरोक्त चौकी का स्थानांतरण कर दिया गया तो इन गांव के ग्रामीण अपने आपको असुरक्षित महसूस करेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि सीलोन जंगली इलाका है यहां आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के कारण पुलिस चौकी से ग्रामीणों को सुरक्षा मिलती है। ग्रामीणों ने कहा कि वर्तमान में केन-बेतवा लिंक डेम बन रहा है जिससे यहां बड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आना-जाना बना रहता है। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि ग्रामीणों की सुरक्षा के चलते चौकी के स्थानांतरण को रोका जाए। इस अवसर पर दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे।

एनसीएल को जीएसटी अनुपालन हेतु मिला उत्कृष्ट पुरस्कार

सिंगरौली। भारत सरकार की मिनीरत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को जीएसटी अनुपालन में उत्कृष्टता और राजकोष में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सीजीएसटी विभाग, जबलपुर द्वारा पुरस्कृत किया गया।इस विशिष्ट उपलब्धि के अवसर पर कंपनी के सीएमडी श्री बी. साईराम और निदेशक (कार्मिक) श्री मनीष कुमार, निदेशक (वित्त) श्री रजनीश नारायण, निदेशक (तकनीकी/संचालन) श्री जितेन्द्र मलिक, निदेशक (तकनीकी/परियोजना एवम्-योजना) श्री सुनील प्रसाद सिंह एवम्-मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री रविन्द्र प्रसाद ने एनसीएल टीम को बधाई दी।एनसीएल को यह पुरस्कार जबलपुर में आयोजित 7वें जीएसटी दिवस समारोह के दौरान प्रधान आयुक्त (आयकर), सीजीएसटी जबलपुर शाखा श्री शांतम बोस द्वारा दिया गया। एनसीएल की ओर से प्रबंधक (वित्त) डॉ. हेमंत सिंधवानी ने इस पुरुस्कार को ग्रहण किया। 7वें जीएसटी दिवस समारोह के दौरान एनसीएल को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6362.28 करोड़ रुपये का योगदान देने के लिए एमपी जोन में अग्रणी जीएसटी भुगतानकर्ता के रूप में सम्मानित किया गया।

गर्भवती महिलाओं की तीन महीने में प्रथम एएनसी की जांच सुनिश्चित कराएं: कलेक्टर

कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केन्द्र समय से खोलने और बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के दिए निर्देश

छतरपुर।

कलेक्टर संदीप जीआर की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग की विभागीय एवं बाल संरक्षण समिति की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में डीपीओ राजीव सिंह, सीडीपीयू, डीपीएम, आंगनबाड़ी सुपरवाईजर एवं कार्यकर्ता, एएनएम, एफएमसीएच एवं केईएफ की टीम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्री जी.आर. ने समीक्षा करते हुए आंगनबाड़ी सुपरवाईजरों को निर्देश दिए कि एक-एक केन्द्र को गोद लें और मॉडल आंगनबाड़ी के रूप में विकसित करें। उन्होंने कहा शादी होकर गांव में आने वाली महिलाओं का डाटाबेस अपने पास रखने के निर्देश दिए। साथ ही समग्र आईडी को तत्काल अपडेट कराने के निर्देश दिए। उन्होंने इस संबंध में निकायों के सीएमओ और जनपद सीईओ को निर्देश किए कि अभियान चलाकर समग्र आईडी के अपडेशन तत्काल होने सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा केन्द्रवार गर्भवती महिलाओं के घर विजिट कर उन्हें प्रथम तिमाही में एएनसी जांच कराने की जानकारी देते हुए अन्य योजनाओं के लाभ के बारे में बताएं। साथ ही एएनसी की शतप्रतिशत जांच होना सुनिश्चित हो।

कलेक्टर ने गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को मिलने वाले शासकीय योजनाओं के लाभ को समय से दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं जननी सुरक्षा योजना सहित अन्य लाभ समय से हितग्राही महिला को मिलना सुनिश्चित हो। उन्होंने बाल शिशु गृह के व्यवस्थित रूप से संचालन कराने के निर्देश दिए।

शादी होने के बाद तत्काल समग्र आईडी में अपडेशन सुनिश्चित कराने के निर्देश -

कलेक्टर ने डीपीओ को निर्देशित किया कि सुपरवाईजरों के लिए एक आंगनबाड़ी केन्द्र में मुख्यालय बनाएं। ताकि कार्य और सुलभ हो सके। उन्होंने आंगनबाड़ी की दिनचर्या के बारे बिन्दुवार समीक्षा की। साथ ही केन्द्रों में हो रही बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में एक दूसरे से शेयर करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री जी.आर. ने आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता और सहायिका को समय से पहुंचने के निर्देश दिए। साथ ही बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए निर्देशित किया। उन्होनें कहा बच्चों को प्राथमिकता शिक्षा के अलावा विभिन्न खेलों की प्रैक्टिस कराएं। जिससे उनके शिक्षा का स्तर बढ़े। बच्चों को मीनू के अनुसार ही पोषण युक्त भोजन नाश्ता खिलाया जाए। बच्चों के भोजन को रंगीन बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा सब्जी, दाल इत्यादि में मुनगा के पत्तों को अनिवार्य रूप से डाले और रोटी में भी पालक को भी मिलाए। उन्होनें कहा प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों में मुनगा के अधिक से अधिक पौधे रोपें। उन्होंने निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की समीक्षा कर जल्द निर्माण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने एनआरसी में कुपोषित बच्चों की शतप्रतिशत भर्ती संख्या बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही सतत निरीक्षण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा बच्चों की भर्ती संख्या कम होने पर संबंधित आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने एनआरसी में कुपोषित बच्चों की शतप्रतिशत भर्ती संख्या बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही सतत निरीक्षण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा बच्चों की भर्ती संख्या कम होने पर संबंधित आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

बेटियों के प्रति माता-पिता को करें जागरूक

आंगनबाड़ी केन्द्रों का सतत निरीक्षण करने के निर्देश -

कलेक्टर ने सीडीपीओ को रेण्डमली आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होनें केन्द्रों स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। साथ ही अनावश्यक सामग्री को कक्षों से अलग करने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर ने अच्छा कार्य कर रहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं सीडीपीओ को पुरस्कृत किए जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ऐसे माता-पिता की प्रशंसा करें। जिन्होंने दो बेटियों को जन्म दिया है। साथ ही बेटियों के प्रति माता पिता को सकारात्मक उद्देश्य से जागरूक करने के निर्देश दिए। बैठक में बक्सवाहा सीडीपीओ के अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने एवं एक वेतन वृद्धि रोके जाने के निर्देश दिए।

नौगांव जनपद पंचायत क्षेत्र की लहादरा पंचायत का मामला ...

3 महीने पहले विधायक निधि से निर्मित समाज भवन की दीवारों में आ रही दरारें

नौगांव। नौगांव जनपद क्षेत्र में ग्राम पंचायत लहादरा के बारबई गांव में विधायक निधि से निर्मित सामुदायिक भवन के निर्माण के 3 महीने बाद ही भवन की दीवारों एवं छत में दरारें आने लगी हैं, जिसके चलते पहली ही बारिश का पानी रिसने लगा तो वहीं दीवारों में दरारें आने से भवन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं।

निवर्तमान विधायक नीरज दीक्षित ने ग्राम पंचायत लहादरा के ग्राम बारबई के ग्रामीणों की मांग पर विधायक निधि से समाज भवन किए 3 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी। जिसके बाद 24 मई 2023 को विधायक निधि से राशि स्वीकृत की गई। विधायक निधि से स्वीकृत राशि से ग्राम पंचायत लहादरा की सरपंच गुलाब कुंवर यादव, सचिव बिहारी लाल अहिरवार, उपयंत्री रामप्रकाश गुप्ता ने बारबई में समाज भवन का निर्माण कराया। सरपंच, सचिव और उपयंत्री की मिलीभगत से राशि ठिकाने लगाते रहे गुणवत्ताहीन मैटेरियल से निर्माण पूरा करा दिया।विधायक निधि की राशि से निर्मित समाज भवन के निर्माण कार्य पूरा होने के अभी लगभग तीन महीने ही गुजरें हैं की समाज भवन में हुए भ्रष्टाचार की पोल खुलने लगी हैं, समाज भवन की दीवारों में दरार आने लगी हैं तो वहीं छत भी रिसने लगी। जिससे सरपंच श्रीमति गुलाब कुंवर यादव और सचिव बिहारी अहिरवार की मिली भगत से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। विदित हो कि उक्त समाज भवन स्वीकृति दिनांक से तैयार होने के तीन महीने बाद ही दीवारों, फाउंडेशन में दरारें आने लगी और छत से पानी टपकने लगा है जो कि ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

शासन की आंखों में धूल झोंक रहे सरपंच सचिव -

ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच सचिव के द्वारा शासन की राशि का दुर्पयोग किया जा रहा है।नियम विरुद्ध तरीके से राशि का आहरण किया जा रहा है। पंचायतों में कराए गए निर्माण कार्य में अधिकांश कार्य ध्वस्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। ग्राम पंचायतों में ऐसे मस्टर भरे जा रहे है जो मजदूरी के नाम से कोसों दूर हैं। भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए पोर्टल पर धुंधले बिल अपलोड किए जा रहे है। आखिर कार अंत में सवाल यही उठता है कि प्रशासन के आला अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी भ्रष्ट सरपंच सचिव पर कार्रवाई करने से क्यों कतरा रहे हैं।

भैरा सरपंच ने बगैर नाली निर्माण किये शासकीय राशि आहरण कर किया दुरुपयोग

लवकुशनगर। जनपद पंचायत लवकुशनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत भैरा में अभी भी शासकीय राशि का दुरूपयोग रुकने का नाम नही ले रहा है। जिसका प्रमुख कारण है, लोगों द्वारा की गयी शिकायतों पर अधिकारियों का कार्रवाई न करना। पूर्व में भी गांव के लोगों ने निर्माण कार्यों और फर्जी बिलों को लेकर लिखित शिकायतें की थी लेकिन आज तक उन शिकायतों का कोई निराकरण नही निकला और फिर एक मामला सामने आ गया। भैरा पंचायत अंतर्गत गांव सिलपतपुरा में ग्राम ई स्वराज योजना के अन्तर्गत नाली निर्माण का कार्य होना स्वीकृत हुआ था। यहां सरपंच/ सेक्रेटरी ने मिलकर शासन की लगभग राशि 1,84,000 रुपए जनवरी 2024 में निकाल ली। इस राशि के अंतर्गत ग्राम सिलपतपुरा वार्ड क्रमांक 17 में मैयादीन अहिरवार के मकान से नीरज पटेल के मकान तक नाली का निर्माण किया जाना था। जो कभी हुआ ही नहीं और राशि आहरण कर ली गयी। इस मामले में राशि के भुगतान में प्रथम बाउचर 27/1/2024 को जो कि बरदानीपाल के नाम से राशि 36000, दूसरा बाउचर 27/1/2024 को नमन ट्रेडर्स के द्वारा राशि 50050 रुपए जबकि तीसरा बाउचर 14/2/2024 को नमन ट्रेडर्स के द्वारा 50050 रुपए आहरण किया गया। इसमें वर्तमान सरपंच शिवराम दीक्षित के घोटाले को उजागर किया गया हैं। ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्य ऐसे ही भ्रष्टाचार की भेट चढ़ रहे है। अपनी जेब गरम करने के चक्कर में सरपंच/सेक्रेटरी ने मिलीभगत से प्रशासन को लाखो का चूना लगाया है। जिसके संबंध में प्रार्थी सविनय उपाध्याय पिता देवकीनंदन उपाध्याय ने पूरे घोटाले की जांच की मांग जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी से आवेदन सौप कर की हैं।

इनका कहना है -

आवेदन प्राप्त हुआ है, टीम बनाकर जांच करा के कार्यवाही की जायेगी।

तपस्या परिहार

जिला सीईओ, जिला पंचायत छतरपुर

केन्द्रीय मंत्री श्रीजी किशन रेड्डी ने निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किया

सिंगरौली। केन्द्रीय कोयला तथा खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने मंगलवार को नई दिल्ली में कोल इंडिया की सीएसआर के तहत "राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों को पुरस्कृत करने की उत्कृष्ट पहल (निर्माण)" पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की "मिशन कर्मयोगी" की परिकल्पना के अनुरूप यह योजना, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपनी गतिविधियों के संचालन वाले जिलों के उन मेधावी युवाओं के लिए शुरू की गई एक अनूठी सीएसआर योजना है, जिन्होंने 2024 में यूपीएससी परीक्षा (सिविल सेवा और वन सेवा) के प्रारंभिक दौर (प्री एग्जाम) में सफलता प्राप्त की है। इस अवसर पर कोयला मंत्रालय के सचिव श्री अमृत लाल मीणा, कोल इंडिया अध्यक्ष श्री पी. एम. प्रसाद, निदेशक (कार्मिक) कोल इंडिया लिमिटेड श्री विनय रंजन, एनसीएल सीएमडी श्री बी. साईराम व कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अन्य कोयला कंपनियों के सीएमडी व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।इस योजना का उद्देश्य प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उन उम्मीदवारों को 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये) की सहायता प्रदान करना है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला या थर्ड जेंडर से संबंधित हैं तथा सीआईएल की गतिविधियों के संचालन वाले 39 जिलों में से किसी एक के स्थायी निवासी हैं। अतः सिंगरौली और सोनभद्र के ऐसे स्थायी निवासी जो इस योजना द्वारा

लाभान्वित होने की पात्रता रखते हैं वे इस नवाचारी पहल का लाभ उठा सकते हैं। इतना ही नहीं आवेदनों की पूर्ण पारदर्शी एवं निर्बाध जांच सुनिश्चित करने हेतु पूरी आवेदन प्रक्रिया एक ऐसे समर्पित पोर्टल के जरिए होगी, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करता है।गौरतलब है कि नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय की एक महारत्न सार्वजनिक उपक्रम है जो न केवल देश की ऊर्जा सुरक्षा की बुनियाद है, बल्कि कोयला धारक क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉरपोरेट की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। "सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास" के जरिए "विकसित भारत" के लक्ष्य को हासिल करने हेतु, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों ने कोयला धारक क्षेत्रों के योग्य एवं वंचित छात्रों को राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित पेशेवर संस्थानों में प्रवेश पाने में मदद करने के लिए विभिन्न योजनाओं को अमल में ला रही हैं।

हरप्रीत कौर ने 80 वर्षीय वृद्ध की सर्जरी के लिए किया रक्तदान

छतरपुर। रक्तदान ऐसी अलख है जिसमे मातृशक्तियाँ भी पीछे नहीं हैं। आपाजी ब्लड ग्रुप के रफत खान ने जानकारी दी कि लवकुशनगर निवासी चिंतामण गुप्ता का ऑपरेशन होना था जिसमे ब्लड की आवश्यकता थी। ब्लड बैंक में उक्त ग्रुप का अभाव था जिसके कारण परिजनों ने सहायता हेतु आपाजी ब्लड ग्रुप से संपर्क किया तब ग्रुप की ओर से यह जानकारी सिविल लाइन में पदस्थ मोहम्मद माशूक अंसारी की पत्नी ग्रहणी हरप्रीत कौर जिन्होंने पूर्व में रक्तदान करने की इच्छा जताई थी को दी गई। उन्होंने तुरंत बिना विलंब किए अपने पति के साथ जिला अस्पताल आकर रक्तदान कर पीड़ित वृद्ध की मदद की ये उनका दूसरा रक्तदान था। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि आप समाजसेवा करना चाहते है तो रक्तदान से बड़ी कोई समाजसेवा नही है सभी को आवश्यकता अनुसार रक्तदान करना चाहिए। आज के रक्तदान में ब्लड बैंक के लैब टेक्नीशियन दिनेश यादव, पूजा खरे, आरक्षक मोहमद माशूक अंसारी और आपाजी ब्लड ग्रुप के रफत खान उपस्थित रहे।

यातायात एवं आरटीओ ने की स्कूल वाहनों की जांच बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई चैकिंग

छतरपुर। छतरपुर कलेक्टर के निर्देश पर स्कूल बसों और टैक्सी वाहनों की आरटीओ विभाग द्वारा जांच की जा रही है। स्कूल बसों को रोककर उनकी फिटनेस, बीमा, दस्तावेज आदि की जांच कर यातायात के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

आरटीओ विभाग के मनीष खरे ने बताया कि स्कूल विद्यालयों में पढने वाले छात्र-छात्राओं के आवागमन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कई दिनों से स्कूल वाहनों की शिकायतें मिल रही थीं। इसी के चलते कलेक्टर के आदेश पर आरटीओ विभाग द्वारा स्कूल वाहनों की चैकिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए वाहनों का फिजिकल वैरीफिकेशन एवं दस्तावेज चैक किए जा रहे हैं। जो बसें नियमविरूद्ध चल रही हैं उन पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि ओवरलोड वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है साथ ही बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निरंतर स्कूल बसों एवं टैक्सियों की जांच की जाएगी। वहीं उन्होंने देरी रोड तिराहे से गुजर रहे वाहनों के दस्तावेज एवं फिटनेस जांची, नियमविरूद्ध वाहन पाए जाने पर चालानी कार्यवाही की गई।

नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में एनसीएल की बड़ी पहल

एनसीएल ने 250 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता के विकास लिए यूपीआरवीयूएनएल के साथ किया एमओयू

सिंगरौली: नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कोयला मंत्रालय की मिनीरत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने बुधवार को सोनभद्र क्षेत्र में 250 मेगावाट की अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया।एनसीएल की ओर से निदेशक (तकनीकी/परियोजना एवं योजना) श्री सुनील प्रसाद सिंह और यूपीआरवीयूएनएल की ओर से निदेशक (तकनीकी) श्री अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने लखनऊ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस पहल से एनसीएल रिहंद जलाशय में 100 मेगावाट तैरता (फ्लोटिंग) सोलर पावर प्लांट और 150 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट की स्थापना करेगी। इस उपलब्धि पर एनसीएल के सीएमडी श्री बी. साईराम ने एनसीएल को नेट-जीरो बनने और सतत खनन के लिए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को अपनाने की कंपनी की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही इस पहल को कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में मजबूत कदम बताया। इस अवसर पर लखनऊ में एनसीएल के महाप्रबंधक (ईएंडएम)/विभागाध्यक्ष श्री दिनेश दंडोतिया, श्री एस एन पांडे, प्रबंधक (ईएंडएम), एनसीएल और श्री शैलेश सिंह, सीई (एमपीएस) और श्री डी के शर्मा, सीई (वाणिज्यिक), यूपीआरवीयूएनएल एवं अन्य उपस्थित रहे। गौरतलब है कि एनसीएल ने निगाही क्षेत्र में 50 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट का संचालन पूर्व में ही चालू कर दिया है। इस परियोजना के अमल में आने के बाद, एनसीएल नेट-जीरो कंपनी बनने के लिए जरूरी लगभग 290 मेगावाट की आवश्यकता को पूरा कर नेट-जीरो कंपनी बन सकेगी।

खबर संक्षेप

न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण में सरकार के लचर रवैये

रीवा। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण के मामले में पहले तो भाजपा सरकार ने 5 वर्ष की

बाध्यता को दरकिनार कर 9 वर्ष में किया और अब उसे कारखाना मालिकों से मिलीभगत कर कानूनी उलझन में फंसाकर मजदूरों से छीनने की साजिश की जा रही है उक्त आशय के आरोप सीटू के जिलाध्यक्ष गिरिजेश सिंह सेंगर, महासचिव सौरभ मिश्र ने लगाते हुये कहा कि इंदौर खण्डपीठ द्वारा दिये स्थगन के आदेश के मामले में 1 जुलाई को हुयी सुनवाई में सरकारी वकील द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के नाम पर न्यायालय से समय मांगा जिससे मामले की सुनवायी स्थगन समाप्त कराने के मामले में सरकार मिलीभगत व टालमटोल का रवैया अपना कर 25 लाख से अधिक श्रमिकों-संविदा कर्मियों के अधिकारों व उनके परिजनों के हितों पर कुठाराघात कर रही। सीटू नेताओं ने कहा कि 7 मई को न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश के बाद पिछली पेशी 21 मई को हुयी तब कारखाना मालिकों ने नये आवेदन लगाकर पेशी बढवा दी और इस बार सरकारी वकील ने प्रस्तुत आवेदनों पर जवाब देने के बहाने पेशी आगे बढवा दी। लाखों मेंजदूरों से जुडे सवाल पर लगभग दो माह की समयावधि में भी यदि सरकार न्यायालय में अपना जवाब प्रस्तुत नही कर पा रही तो इससे सरकार की मंशा उजागर हो जाती है। सीटू के नेताओं ने कहा कि मजदूरों के वैधानिक अधिकारों की इस लडाई में यदि सर्वोच्च न्यायालय भी जाना पडेगा तो सीटू जायेगी। सीटू के नेताओं ने कहा कि सरकार के इस लचर रवैये व मालिकों से मिलीभगत के चलते प्रदेश भर के मजदूरों में भारी असंतोष है। इस मामले में प्रदेश में हडताल करने से लेकर सर्वोच्च न्यायलय तक जाने के लिये हम मजदूरों को तैयार कर रहे है।

जिला लोकल लेबल कमेटी की बैठक संपन्न

रीवा। राष्ट्रीय न्यास लोकल लेबल कमेटी की बैठक अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में विधिक संरक्षकता के आवेदनों पर विचार एवं नियुक्ति के दौरान कुल प्राप्त 12 आवेदनों में से 11 आवेदनों का अनुमोदन किया गया। कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय न्यास निरामया योजनान्तर्गत 150 हितग्राहियों का बीमा कराया गया है। इस अवसर पर निर्देश दिये गये कि लोकल गार्जियन के आवेदन पूर्ण परीक्षणोपरांत ही अनुमोदित कराये जांय। बैठक में संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे, डॉ. प्रभाकर चतुर्वेदी, ए.के. खान, के.पी. गुप्ता, विनोद श्रीवास्तव, संतोष अवधिया, शशिधरमणि त्रिपाठी, दिवाकर सिंह तथा रामजी पाण्डेय उपस्थित रहे।

ससुराल में महिला की संदिग्ध मौत

रीवा। शहर के बिछिया थाना क्षेत्र में एक नव ब्याहता की ससुराल में हुई संदिग्ध मौत के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ।परिजनों का आरोप है कि दहेज के लिए उनके बेटी की हत्या की गई है जिसे लेकर परिजन अब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। घटना को लेकर परिजनों के द्वारा मृतका के पति सहित सास ससुर एवम परिवार के अन्य सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए हैं । घटना बिछिया थाना क्षेत्र के महाजन टोला की है इस संबंध में मृतका के पिता बृजभान द्विवेदी ने बताया कि मनगवा निवासी कंचन त्रिपाठी का विवाह महाजन टोला के सुशील त्रिपाठी के साथ हुआ था जिसमें काफी दहेज भी दिया गया था परिजनों का आरोप है कि विवाह के तकरीबन 5 साल बीत जाने के बाद भी उसके ससुराल वाले दहेज के लिए आए दिन मारपीट करते थे विवाद की स्थिति को देखते हुए मृतिका कंचन त्रिपाठी काफी समय तक अपने मायके में भी रही परिजनों का कहना है कि बीती रात विवाद की स्थिति को देखते हुए मृतिका कंचन त्रिपाठी अपने मामा ससुर के यहां फरियाद लेकर गई थी जिसकी जानकारी मृतिका के द्वारा अपनी मां को भी दी गई लेकिन सुबह पता चला कि कंचन त्रिपाठी की मृत्यु हो गई है विवाद की स्थिति को देखते हुए पुलिस दोनों ही पक्षों को समझाइए दिया।

मध्यप्रदेश के विकास को नई ऊर्जा प्रदान करेगा बजट: उप-मुख्यमंत्री

प्रदेश के समग्र विकास को समर्पित बजट के लिए व्यक्त किया आभार

उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल व दक्ष नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था में निरंतर विस्तार हो रहा है। भारत आज विश्व 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।

रीवा !

वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार अपना योगदान सुनिश्चित कर रही है। यह प्रसन्नता का विषय है कि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 16 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। यह बजट मध्यप्रदेश के विकास को नई ऊर्जा प्रदान करेगा विकास की गति को तेज़ करेगा। उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सर्व जनहिताय, विकासोन्मुख बजट के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और उप-मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का आभार व्यक्त किया है।

कुशल वित्तीय प्रबंधन से हर क्षेत्र में संसाधन की उपलब्धता

उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि कुशल वित्तीय प्रबंधन से प्रदेश के समग्र विकास हेतु हर क्षेत्र में संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है। शिक्षा व स्वास्थ्य, युवा और महिला सशक्तिकरण, सामाजिक उत्थान, अधोसरंचनाओं का विस्तार, रोजगार-स्वरोजगार के अवसर, औद्योगिक विकास आदि के साथ-साथ पर्यावरण, संस्कृति के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधनों का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा है कि बजट, प्रदेश को विकसित बनाने के प्रयासों को और अधिक सफल व परिणामजनक बनाएगा।

आगामी वर्षों में 11 नये शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय होंगे संचालित

उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि चिकित्सकीय सेवाओं के प्रदाय के लिए चिकित्सकीय मैनपॉवर की पर्याप्त उपलब्धता महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार चिकित्सा शिक्षा की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास कर रही है। प्रदेश में वर्ष 2003 में मात्र 5 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय ही संचालित थे। सरकार के अथक प्रयासों से वर्तमान में 14 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित हैं। वर्ष 2024-25 में 3 और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय -मंदसौर, नीमच एवं सिवनी में संचालित हो जायेंगे। इसके पश्चात आगामी 2 वर्षों में 8 और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित करने हेतु भी हमारी सरकार प्रयासरत है। नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन के उपरांत नवीन सीटों की संख्या स्नातक स्तर पर 3 हजार 605 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर एक हजार 507 हो जायेंगी।

आयुष्मान योजना का दायरा विस्तृत

योजना के लिए 45 प्रतिशत से अधिक बजट प्रावधानित - उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सभी नागरिकों तक बेहतर चिकित्सा सुविधा के दृष्टिगत आयुष्मान भारत योजना का दायरा और भी अधिक विस्तृत किया है। अब तक लगभग एक करोड़ 8 लाख परिवारों के 4 करोड़ एक लाख सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान हितग्राहियों के लिये नवीन हेल्थ बेनिफिट पैकेज–2022 लागू किया गया है, जिसमें पूर्व की एक हजार 670 चिकित्सा प्रक्रियाओं को विस्तारित करते हुये अब एक हजार 952 प्रक्रियाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभांवित किया जा रहा है। राज्य में अब एक हजार से भी अधिक चिकित्सालय योजना के अंतर्गत संबद्ध हैं। आयुष्मान भारत योजना के लिए रूपये एक हजार 381 करोड़ का प्रावधान है, जो गत वर्ष की तुलना में 45 प्रतिशत अधिक है।

हर नागरिक तक निःशुल्क जाँच सेवा के प्रयास

प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में उपचार के दौरान दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाने पर पार्थिव शरीर, परिजनों को सम्मानपूर्वक सौंप कर, घर तक पहुंचाने के लिये ''मध्यप्रदेश शांति वाहन सेवा'' प्रावधानित है। गंभीर रोगियों को आपात स्थिति में उचित समय पर उच्च स्तरीय चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने हेतु ''पी.एम. श्री एअर एम्बुलेंस सेवा'' योजना प्रारंभ की गई है। राज्य के नागरिकों को निःशुल्क जाँच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निजी-भागीदारी के माध्यम से "वेट लीज मॉडल" अंतर्गत जिला चिकित्सालयों में 132 प्रकार की, तथा "हब एण्ड स्पोक मॉडल" के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 45 प्रकार की जाँच सुविधायें उपलब्ध करायी गई हैं। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्कृष्ट और सहजता से उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार कृत-संकल्पित है।

स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में 34 प्रतिशत वृद्धि

उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सशक्त विकसित प्रदेश के लिए नागरिकों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। इसे प्राथमिकता देते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 हेतु रूपये 21 हजार 444 करोड़ का प्रावधान किया है, जो कि वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान से 34 प्रतिशत अधिक है। उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं में निवेश को निरंतर बढ़ा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिए इण्डियन पब्लिक हेल्थ स्टेण्डर्ड के मापदंडों को लागू किया जा रहा है। सरकार ने 46 हजार से अधिक नवीन पदों का सृजन किया गया है। आगामी 2 वर्षों में इन पदों की पूर्ति के प्रयास हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापक पहुंच हो, इसलिए संस्थागत व्यवस्था को भी मजबूत बनाया गया है।

परिवहन विभाग ने लगाया लर्निंग लाइसेंस का शिविर

रीवा ।

परिवहन विभाग रीवा के द्वारा शासन की मंशानुशार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आई टी आई रीवा में निःशुल्क लाइसेंस शिविर लगाया गया।जिसमें संस्थान से कोपा, इलेक्ट्रीसियन, इंगलिश हिन्दी शार्टहैंड आदि के कई सारे ट्रेड के विद्यार्थी थे। जिनमे लड़कियों के लाइसेंस का कोई शुल्क नहीं था।शिविर 12 बजे से शुरू किया गया। जिसमें प्राचार्य श्री मिश्रा के द्वारा स्मार्ट क्लास उपलब्ध कराई गई,जहां पर बच्चों को परिवहन विभाग के द्वारा प्रशिक्षित किया गया और लड़कियों को लर्निंग लाइसेंस बनाकर प्रदान किया गया। बुधवार को 104 लर्निंग लाइसेंस बनाये गए। अगला शिविर दिन गुरुवार दिनांक 4/07/2024 को न्यू मॉडल साइंस कालेज रीवा जिसका वर्तमान नाम शासकीय एम एस गोलवरकर कालेज रीवा है, में दोपहर 12 बजे से लगाया जायेगा।

रीवा नगर निगम की सख्ती 18 कॉलोनाइजरों पर 51.60 करोड़ का जुर्माना, नोटिस जारी

रीवा।

जिले की नगर निगम प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे ने प्रभार संभालते ही इस बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे और अब इस पर अमल कर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। पहले चरण में पूर्व में वैध की गई 18 कॉलोनियों के कॉलोनाइजरों को जुर्माने का नोटिस भेजा गया है। इन कॉलोनाइजरों पर 51.60 करोड़ का जुर्माना निगम ने ठोका है। इनको नोटिस जारी कर दिए गए है और जुर्माना राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस जारी होते ही इन कॉलोनियों को बसाने वाले कॉलोनाइजरों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं निगम प्रशासन इन कॉलोनाइजरों को किसी प्रकार की कोई राहत देने को तैयार नहीं है।मिली जानकारी के मुताबिक बीते वर्ष नगर निगम द्वारा शहर में करीब 109 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर वैध किया था। जिसमें शासन के

नियमानुसार विकास शुल्क जमा कराकर उनको भवन अनुज्ञा सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अभी तक इनको बसाने वाले अवैध कॉलोनाइजर बचे हुए थे लेकिन अब उन पर गाज गिरना शुरू हो गई है। करीब 71 कॉलोनाइजरों पर 121 करोड़ से अधिक का जुर्माना तय कर लिया गया है, जिसमे 18 को नोटिस जारी किए गए हैं। महापौर अजय मिश्रा बाबा ने बताया कि अवैध कॉनोनियों पर कार्रवाई की जा रही है, इसके साथ ही पूर्व में जिन अवैध कॉलोनियों को वैध किया गया है, उन्हें बसाने वालों पर भी जुर्माना किया गया है। नोटिस जारी किए गए हैं।

इनका कहना है

कॉलोनियों में पार्क के लिए 10 प्रतिशत भूमि को आरक्षित किया जा रहा है, जहां भूमि नहीं हैं। वहां कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। अभी तक 18 कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनसे वसूली की जाएगी। अन्य को नोटिस जारी किया जा रहा है।

एच के त्रिपाठी कार्यपालन यंत्री नगर निगम रीवा

चोरों ने व्यापारी के घर से सोने के गहने सहित कई लाखों की नकदी ले कर हुए फरार

रीवा।

जिले के अतरैला बाजार स्थित एक घर से चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान चोर सोने के गहने व 1.50 लाख की नकदी चोरी कर फरार हो गए। घटना के संबंध में पीड़ित रामशंकर सोनी उर्फ राजा पुत्र राजबली सोनी निवासी अतरैला बाजार ने बताया कि गत दिन वह अपने परिवार के साथ दक्षिण भारत तीर्थ यात्रा में गए हुए थे। जब कल सुबह 11 बजे घर वापस आए तो देखा कि घर के सभी दरवाजे खुले हुए थे और अंदर पड़ा हुआ सामान बिखरा हुआ था। उन्होंने बताया कि चोर घर के लोहे का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए और घर में पड़ी अलमारियों का लॉक तोड़कर उसमें से एक सोने का सेट, 3 सोने की अंगूठियां, 2 जोड़े

सोने की बालियां एक मंगलसूत्र 22 ग्राम का व 1.50 लाख रुपए चोरी कर फरार हो गए। अज्ञात चोरों ने करीब दस लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया हैं पीड़ित ने बताया कि उन्होंने थाना अतरैला पुलिस को सूचित कर दिया है। दूसरी तरफ घटना की सूचना मिलने के बाद थाना अतरैला की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लेने के उपरांत मामले की जांच शुरू कर दी है।

प्रदेश को विकसित बनाएगा, हर वर्ग के जीवन में खुशियां लाएगा नया बजट : जनार्दन मिश्रा

रीवा ।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत वर्ष 2024-25 के बजट का स्वागत करते हुए कहा कि 3 लाख, 65 हजार, 67 करोड़ रुपये का यह बजट अब तक का सबसे बड़ा एवं ऐतिहासिक बजट है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार द्वारा प्रस्तुत यह बजट कुशल आर्थिक प्रबंधन की मिसाल है। भाजपा सरकार का फोकस हमेशा से विकास पर रहा है और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखकर प्रदेश का चहुंमुखी विकास कर रही है। उनकी सरकार द्वारा प्रस्तुत यह सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय बजट प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेगा। यह बजट मध्यप्रदेश के युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों के साथ समाज के हर वर्ग को ताकत देने वाला है, जिसमें गरीब कल्याण का ध्यान रखा गया है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वादा, युवाओं को रोजगार : राजेंद्र मिश्रा

भाजपा मऊगंज जिला अध्यक्ष डॉ राजेंद्र मिश्रा ने प्रदेश सरकार के प्रस्तुत बजट को जन सामान्य की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट निरूपित करते हुए कहा है किकांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं के साथ धोखा किया है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने प्रदेश के युवाओं से जो वादे किए थे, उनमें से किसी वादे को पूरा नहीं किया। वहीं भाजपा की सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए हर हाथ को काम की अवधारणा पर कार्य कर रही है। युवाओं को तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने युवाओं, व प्रदेश की जनता से बेहतर व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं रोजगार का जो वादा किया था, वह उसे पूरा करने की ओर अग्रसर है। प्रदेश में बच्चों के सर्वांगीण विकास की सोच के साथ सी.एम राईज योजना शुरू की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत लगभग 150 सी.एम राईज विद्यालय नवीन भवन में संचालित होंगे। सी.एम.राईज विद्यालयों के लिये रूपये 2 हजार 737 करोड़ का प्रावधान है। शासकीय स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता के साथ खेल, नृत्य, संगीत शिक्षकों के 11 हज़ार पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

मऊगंज के चार सहायक उपनिरीक्षक पदोन्नत

सहायक उपनिरीक्षक से कार्यवाहक उप निरीक्षक बने

मऊगंज।

मध्य प्रदेश सरकार पुलिसकर्मियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। और अब इन पुलिसकर्मियों के खुशी का ठिकाना नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने सहायक उप निरीक्षक को सब इंस्पेक्टर पद का कार्यवाहक प्रभार सोपा गया है इन पुलिस कर्मियों को उनकी वरिष्ठता और कुशल कार्यशैली के आधार पर प्रमोट किया गया है मऊगंज जिले के जिला मुख्यालय अंतर्गत 04 सहायक उप

निरीक्षक को कार्यवाहक उपनिरीक्षक पर पदोन्नति हुई है मऊगंज जिला मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने सहायक उपनिरीक्षक अनंत विजय सिंह, संतोष सिंह चौहान, अनंत मिश्र एवं अंगद प्रसाद शुक्ला के कंधे पर स्टार लगाकर बधाई दी।इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हर पुलिसकर्मी का सपना होता है कि वो दरोगा बने।वही प्रमोशन मिलने के बाद सभी पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि प्रमोशन पाने वाले सभी पुलिसकर्मी और अधिक निष्ठा व कर्तव्यों को पालन करेंगे।

रिहंद जलाशय में तैरेगा एनसीएल का विशालकाय सोलर पावर प्लांट

मऊगंज। नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कोयला मंत्रालय की मिनीरत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने बुधवार को सोनभद्र क्षेत्र में 250 मेगावाट की अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया।एनसीएल की ओर से निदेशक (तकनीकी/परियोजना एवं योजना) श्री सुनील प्रसाद सिंह और यूपीआरवीयूएनएल की ओर से निदेशक (तकनीकी) श्री अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने लखनऊ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस पहल से एनसीएल रिहंद जलाशय में 100 मेगावाट तैरता (फ्लोटिंग) सोलर पावर प्लांट और 150 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट की स्थापना करेगी।

वार्डों की नालियों से बरसाती पानी निकासी ठप्प

मऊगंज। नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत सभी वार्डों में बरसाती पानी के निकासी की नालियां मिट्टी व कचड़े के ढेर से भरी हुई है। जिससे बरसाती पानी का निकास रुका हुआ है।सनद रहे कि प्रत्येक वार्ड में कम से कम तीन मोहल्ला की बस्ती है सभी मोहल्ले में नालियां मिट्टी व कचड़े के ढेर से भरी हुई है जिससे बरसाती पानी की निकासी नहीं होगी और बरसाती पानी घरों में प्रवेश करेगा और आमरास्ता में जमा होगा। जिससे मच्छर जनित बीमारी सामूहिक रूप से फैलेगी। उक्त गंभीर समस्या के प्रति नगर पंचायत के अधिकारी व कर्मचारी अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हैं क्षेत्र के सामाजिक

कार्यकर्ता गणो ने माननीय कलेक्टर मऊगंज से हस्ताक्षेप कर अविलंब उचित व्यवस्था बनाए जाने की गुजारिश की है। उक्त मांग करने वालों में रेल लाओ जिला बनाओ मंच के अध्यक्ष शिव शंकर मिश्र बरहटा, अधिवक्ता संघ मऊगंज के पूर्व उप अध्यक्ष ममनून सिद्दीकी, सेवा निवृत्त प्राचार्य रामनिश्चय मिश्र, डॉ चंद्रमा प्रसाद मिश्र, सीताराम गुप्ता, उमा गुप्ता, भगवान प्रसाद अवधिया, शैलेन्द्र सिंह गहरवार, आनंद तिवारी, गिरजा शंकर गुप्ता, जयदीप श्रीवास्तव, शशिभूषण सिंह परिहार ने नगर पंचायत मऊगंज के सभी वार्डो की नालियों की सफाई व मरम्मत कराये जाने हेतु कलेक्टर से हस्ताक्षेप करने की मांग की है।